

# और तेज होगी धान की खरीद

पटना, जागरण ब्यूरो: सूबे में अब तक विभिन्न एजेंसियों के जरिये तकरीबन 45 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। लक्ष्य तीस लाख मिट्रिक टन खरीद का है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि धान खरीद में तेजी लाने के हर संभव प्रयास किये जायें।

सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्याम रजक ने प्रधान सचिव, राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ धान खरीद की प्रगति एवं ई-पीडीएस के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने निदेश दिया कि किन्हीं कारणों से अगर पैक्स किसानों से धान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किसानों को राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर धान देने की सुविधा होनी चाहिये। ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने प्रबंध निदेशक राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया कि सभी केन्द्रों पर मायश्चर (नमी) मीटर लगायी जाये, ताकि धान में कितनी नमी है इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से धान खरीद की मानीटरिंग के लिए

- ◆ अब तक हो चुकी 45 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद
- ◆ हर क्रय केन्द्र पर लगेगा मायश्चर मीटर
- ◆ शुरू होगा 2 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड धारकों की डाटा इंट्री का काम
- ◆ विभाग ने किया 13 करोड़ रुपये का प्रावधान



प्रतिनियुक्त पदाधिकारी लगातार अपने-अपने निर्धारित मंडलों का दौरा करें। धान अधिप्राप्ति एजेंसियों को देय आकस्मिक व्यय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दरे सूचित की जा चुकी है। इसलिए अब धान खरीद में किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिये। श्री रजक ने राज्य में ई-पीडीएस के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्य के करीब 2 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड धारकों की डाटा इंट्री कार्य अविलम्ब शुरू करने को कहा। प्रधान

सचिव ने बताया कि एनआईसी द्वारा डाटा इंट्री फारमेट उपलब्ध करा दिया गया है। इस काम के लिए प्रखंड स्तर पर डाटा इंट्री आपरेटर की प्रतिनियुक्ति के लिए बेल्टान से समन्वय किया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराइजेशन, खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की मानीटरिंग के लिए ई-पीडीएस के संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। इस वित्तीय साल में इन कार्यों के लिए विभाग के स्तर पर करीब 13 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया गया है।